

विकास और आईटी का झुनझुना

दिनेश सी शर्मा

बैंगलूर से ४०-५० किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव थुंउला। गांव की डकलौती प्राइमरी स्कूल के एक कमरे में कुछ बच्चे बैठे हैं। वहां पर तीन चार कम्प्यूटर रखे हैं और उन पर बच्चे कुछ देख रहे हैं, खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खिड़कियों से झाक रहे हैं। यह एक कम्प्युनिटी लर्निंग सेंटर है। कर्नाटक सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मिल कर इस तरह के हजारों केंद्र सारे राज्य में खोलना चाहते हैं। ये केंद्र उन स्कूलों में खोले जा रहे हैं जिनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं और जहां स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की दर (ड्रॉपआउट रेट) काफी अधिक हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन स्कूलों में इस तरह के केंद्र खुले हैं वहां बच्चे और उनके मां-बाप स्कूल और पढाई में ज्यादा रूचि लेने लगे हैं।

दक्षिण के ही पांडिचेरी में कई जगह ऐसे सूचना केंद्र बने हैं जिनसे ग्रामीण महिला और पुरुष अपनी मनचाही जानकारी स्थानीय भाषा तमिल में हासिल कर सकते हैं। यहां पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और रोजगार संबंधी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। कृषि संबंधी सारी स्थानीय जानकारी भी मिल सकती हैं। और यदि आपको गाय या बैल बेचना या खरीदना हो तो उसका इशतिहार भी इंटरनेट पर दे सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सवाल जवाब भी ग्रामीणों में काफी लोकप्रिय है। इन सूचना केंद्रों का सारा तानाबाना मद्रास स्थित एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। डॉ. स्वामीनाथन अब इंटरनेट पर ग्रामीण और कृषि शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी खोलना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश में 'ज्ञानद्रुत' योजना के तहत आम लोगों को सूचनाएं और सेवाएं देने की शुरुआत हुई है। इसके तहत सूचना केंद्र या इनफार्मेशन किओस्क स्थापित किए गए हैं, जहां पर ग्रामीण एक छोटी सी फ़ीस (५ से २० रू. के बीच) देकर विभिन्न दरखाजों की नकल प्राप्त कर सकते हैं। इस काम के लिए जिला मुख्यालय जाने और ऊपर का पैसा देकर काम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सोयाबीन, गन्ना और कॉफी उत्पादक किसानों के लिए कुछ बड़ी कंपनियों ने इंटरनेट सूचना केंद्र खोले हैं। इनके जरिए वे किसानों से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं, ताकि उन्हें उनकी फसल का निश्चित दाम मिल सके। विचौलियों पर निर्भरता नहीं रही। कहीं कहीं पर तो इससे किसानों की आमदनी में १५ प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। निश्चित ही कंपनियों को भी इस व्यवस्था से फायदा है। किस इलाके से कितनी फसल आ सकती है, इसके हिसाब से वे दाम निश्चित करती हैं और अपनी उत्पादन और मार्केटिंग व्यवस्था भी तैयार कर सकती हैं।

ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। इस तरह के प्रयोग आज देश के लगभग हर कोने में हो रहे हैं। इस लहर को नया नाम भी दिया जाने लगा है- विकास के लिए सूचना व संचार टेचनालोजी या “आईसीटी फॉर डेवलपमेंट”। आईसीटी यानि इनफार्मेशन एंड कम्प्युनिकेशन टेचनालोजी। इस विषय पर बड़े बड़े राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सेमिनार हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रही हैं। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इन योजनाओं के लिए पैसा दे रही हैं। कई फाईव-स्टारी गैर सरकारी संगठन भी आईसीटी की इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विकास की चर्चा में आईसीटी का नया फ़ैशन चल निकला है।

विकास में नई टेकनोलॉजी की वया भूमिका हो सकती है यह जांवने के पहले जान लें कि यह आईसीटी बला वया है। १९७० और १९८० के दशक में उपग्रह टैक्नॉलॉजी से आए बदलावों को संचार क्रांति या कम्प्यूनकेशन रिवोल्युशन का नाम दिया गया। मुख्य रूप से इस दौरान टेलिफोन और टेलिविज़न सेवाओं का विस्तार हुआ। आपस में दूरियां कम हुईं और हम “ग्लोबल विलेज” की परिकल्पना की और बढ़े। १९८० के दशक में एक नई टेक्नॉलॉजी उभरी-इनफार्मेशन टेक्नॉलॉजी या सूचना तकनीकी। इस दौर के इलैक्ट्रॉनिक रिवोल्युशन कहा गया। जिसके चलते भीमकाय कम्प्यूटर का आकार घटकर टेबल पर रखे जाने वाले पीसी या पर्सनल कम्प्यूटर का हो गया। पीसी के अतारण के साथ ही उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण होने लगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सम्मिश्रण को नाम दिया गया - आईटी। लेकिन टेक्नॉलॉजी की आंधी आईटी पर नहीं रूकी। १९९० के दशक के मध्य में एक और भारी बदलाव आया। इंटरनेट के रूप में। इसके मूल में थी नेटवर्किंग यानि कि जो अलग-अलग कम्प्यूटर फेले हुए थे उन्हें इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया। इस विश्वव्यापी मकड़जाल को कहा गया - वर्ल्ड वाईड वेब।

जैसा कि नाम से साफ है आईसीटी में संचार और सूचना दोनों का मिश्रण है। निसदेह - आईटी और कम्प्यूटर इसका मुख्य हिस्सा है, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है। आईसीटी काफी व्यापक है - इसमें उपग्रह से लेकर सेल फोन और सामान्य फोन तक की सारी संचार प्रणालियां, उपकरण और टेक्नॉलॉजी शामिल हैं। मुख्य उपकरणों में कम्प्यूटर, पर्सनल डिजिटल अरिस्टैट, टच स्क्रीन किओस्क, सेलफोन, सर्टेलाईट फोन, रेडियो, नोट बुक कम्प्यूटर, टेबलट पीसी आदि आदि शामिल हैं। और इन्हें जोड़ने के लिए उपयुक्त प्रणालियों में फाईबर ऑप्टिक, उपग्रह, बेतार, स्थानीय बेतार लूप और आम टेलीफोन तार शामिल हैं। और इन सब उपकरणों और संचार प्रणालियों को उपयोगी बनाता है सॉफ्टवेयर। इस तरह आईसीटी के तीन भाग साफ हैं - हार्डवेयर यानि उपकरण, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग या जोड़ने की टेक्नॉलॉजी।

वास्तव में देखा जाए तो आईसीटी का दोहन भारत के लिए नया नहीं है । १९८० के दशक में विकसित सी-डॉट ग्रामीण टेलिफोन एक्सचेंज इसका अच्छा उदाहरण है। डाक्टर सैम पिट्रोडा के नेतृत्व में बने सेंटर फॉर-डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिवस ने पहली बार एक ऐसा टेलिफोन एक्सचेंज बनाया जो भारत के गांवों के लिए उपयोगी था। इसकी क्षमता कम थी, बिना एयर कंडिशनर के काम कर सकता था और विजली की कमी होने पर बैटरी के सहारे या सौर ऊर्जा से भी काम कर सकता था। और कीमत भी विदेशी एक्सचेंजों के मुकाबले काफी कम थी। कुल मिलाकर एक भारतीय समस्या का विशुद्ध भारतीय हल था। इस एक्सचेंज ने काफी सफलता पाई और कई ग्रामीण क्षेत्रों में फोन पहुंचे। निश्चित ही इस टेक्नॉलॉजी का गांव पहुंचने से ग्रामीणों को फायदा हुआ। हालांकि इसका कोई ठोस आंकलन नहीं हो पाया लेकिन लाभ तो हुआ ही। संचार मंत्री रहे राजेश पायलट अवसर अपने चुनाव क्षेत्रा दौसा का उदाहरण दिया करते थे कि किस तरह इस टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल वहां के ग्वाले कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली के बड़े मिठाई घरों को दूध सप्लाई करते हैं। रोज रेल से आते जाते हैं। यदि कोई ट्रेन देरी से चल रही हो या छूट जाती तो वे दिल्ली देरी से पहुंच पाते, और तब तक उनके दूध की मांग यहां नहीं रहती। टेलीफोन आने के बाद वे तत्काल दिल्ली सूचित करने लगे कि कितने बजे दूध पहुंच रहा है। इस तरह के और भी उदाहरण हैं।

सी-डॉट की सफलता से प्रेरित होकर मद्रास के भारतीय टेक्नॉलॉजी संस्थान (आईआईटी) के एक प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने दूरसंचार की देसी टेक्नॉलॉजी का विकास किया है। डॉ. झुनझुनवाला के ग्रुप ने ऐसी बेतार टेलीफोन प्रणाली विकसित की है, जिसके जरिए बेतार या वायरलेस के जरिए गांव में घर-घर में फोन पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं एक ही फोन में बातचीत के साथ-साथ इंटरनेट की व्यवस्था भी हो सकती है। इसे कॉरडेवट का नाम दिया गया है। अभी तक भारत सहित कई विकासशील देशों में इस प्रणाली पर आधारित दस लाख लाइनें लग चुकी हैं।

प्रोफेसर झुनझुनवाला मानते हैं कि कॉरडेवट भारत के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में सामाजिक बदलाव ला सकता है। चीन की तरह - जहाँ हर महीने लगभग पचास लाख नए वायरलेस फोन लगते हैं - भारत भी अपना टेलीफोन तंत्र फटाफट बढ़ा सकता है। अपने आप में ये एक उद्योग बना जाएगा - फोन की मांग बढ़ेगी, फोन सेवा प्रदान करने की नई कंपनियां बनेंगी, फोन की फैक्टरियों में लोगों को रोजगार मिलेगा। हर जगह इंटरनेट उपलब्ध होने से सॉफ्टवेयर विकास या कॉल सेंटर जैसी सेवाओं का विस्तार करवों तक हो जाएगा। कुल मिलाकर रोजगार के भारी अवसर बढ़ेंगे और साथ ही आर्थिक संपन्नता। प्रोफेसर झुनझुनवाला कहते हैं कि जिस तरह देश में केवल आपरेटों का धंधा बढ़ा, बिना किसी सरकारी रेगुलोक के, उसी तरह वायरलेस टेलीफोन सेवाओं का पूरी तरह विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए।

ये तो हुई बात टेलीफोन या संचार प्रणाली की कमी को दूर करने की। अब देखते हैं हार्डवेयर की स्थिति। इंटरनेट के लिए जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की जो आज भी एक आम भारतीय की पहुंच के बाहर की चीज है। आईटी तक पहुंच की लागत भारत में अब तक काफी ज्यादा है। कीमतों में कमी के बावजूद अब भी कोई भी पीसी २५ हजार रुपए से कम मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बंगलूर स्थित ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस’ के कंप्यूटर साइंसेज विभाग के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक ऐसा उपकरण ईजाद किया है जिसने पहली बार कीमत की इस बड़ी अड़चन को दूर करने में सफलता पाई है। उन्होंने कम कीमत में इंटरनेट पर पहुंच रखने वाले उपकरण (पर्सनल कंप्यूटर नहीं) का आविष्कार किया है जो मात्र १० हजार रुपए में उपलब्ध हो सकता है। अगर इसे खरीदने वालों की संख्या बढ़ी तो इसकी कीमत में और भी कमी आ सकती है। इसे ‘सिम्यूटर’ या सिंपल कंप्यूटर कहा जाता है।

भले ही यह कंप्यूटर की तरह न दिखे, सिम्यूटर कम कीमत वाला पर्सनल कंप्यूटर है। इसमें न तो की-बोर्ड होता है न बड़े टेलीविजन की तरह विशाल स्क्रीन मॉनीटर। इसमें छोटा संवेदनशील स्क्रीन होता है। जिसमें स्पर्श से हरकत आ आती है और इस्तेमाल करने वाला पेन जैसे उपकरण की सहायता से अपना संदेश लिख सकता है। इसमें की (बटनों) को दबाने की आवश्यकता नहीं होती और न ही एक जगह से दूसरी जगह ‘माउस’ को घुमाने की जरूरत होती है। केवल अपनी उंगलियों के प्रयोग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद के संस्करण शायद ध्वनि सुनकर ही कार्यशील हो जाएं। इसमें स्क्रीन को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी केवल इसके सामने बोलें और बाकी सारा काम यह खुद ही कर देगा। सिम्यूटर ओपेन लाइनेक्स प्लेटफार्म के निशुल्क सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। पर्सनल कंप्यूटर की कीमत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यह माइक्रोसॉट वाले आपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं।

सिम्यूटर एक समुदाय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटिंग उपकरण है। कोई भी स्थानीय समुदाय जैसे कि ग्राम पंचायत या ग्राम विद्यालय या कोई दुकानदार भी इस उपकरण को कुछ निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति विशेष को दे सकता है और उसका काम हो जाने पर समुदाय के किसी और जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि इस उपकरण में व्यक्ति विशेष की बदलती जरूरतों के अनुसार परिवर्तन लाया जा सके। स्मार्ट कार्ड के उपयोग से सिम्यूटर में यह काम भी संभव कर दिया गया है। स्मार्ट कार्ड पर उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल को स्टोर कर सकता है, जो हमेशा उसके साथ होता है। फिर जैसे ही स्मार्ट कार्ड इंटरफेस को उसमें भीतर घुमाया जाता है, सिम्यूटर स्मार्ट कार्ड से उस प्रोफाइल को पढ़ लेता है और अगर उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं तो उनको भी शामिल कर लेता है।

सिम्यूटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य एप्लीकेशन माइक्रो बैंकिंग, कृषि जानकारी, मौसम के बारे में सूचना तक पहुंच, दूरस्थ शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का संकलन और साधारण इंटरनेट ब्राउजिंग आदि हो सकता है। सुरक्षित बैंकिंग सोल्यूशन के लिए सिम्यूटर एक आदर्श गतिशील प्लेटफार्म साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए महााष्ट्र में कई छोटे सहकारी बैंकों ने पहले से ही ग्रामीण ग्राहकों को उनके दरवाजों तक जाकर सुविधाएं मुहैया कराना शुरू कर दिया है। वे अपने साथ कारोबारी प्रिंटर के साथ-साथ एक छोटा पोर्टेबल उपकरण लेकर चलते हैं जो ग्राहकों को बैंक के साथ लेन-देन करने में मदद करता है और उन्हें तत्काल हाथों हाथ इसकी रसीद भी मिल जाती है। सिम्यूटर इस कार्य को ज्यादा कारगर तथा सुरक्षित तरीके से अंजाम दे सकता है।

विकास के लिए आईसीटी के त्रिकोण का तीसरा कोण है कंटेट या सूचना सामग्री और आज की स्थिति में यही सबसे कमजोर कड़ी है। भारत के पास सिंप्यूटर जैसा सस्ता उपकरण है, बेतार से गांव-गांव तक टेलीफोन और इंटरनेट पहुंचाने की टेक्नॉलॉजी है। कमी तो इंटरनेट पर भारतीय कंटेट की, सूचनाओं और सेवाओं की ग्रामीण समाज के लिए उपयोगी हों। यह एक विडंबना है कि “सॉफ्टवेयर सुपर पावर” बनने के सपने देखने वाले देश में उसके लोगों के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की कमी है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी सुधारनी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंप्यूटर के जरिए इंटरनेट तक सरती पहुंच बनाने की उपयोगिता ही वया रह जाती है जब हमारे ग्रामीण लोगों के लिए इंटरनेट पर कोई लाभदायक जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। अगर सिम्यूटर का प्रयोग सफल रहता है तो वया यह गरीब तथा विकासशील देशों में आईटी तक पहुंच बनाने संबंधित हमारी कई समस्याओं का निराकरण कर सकता है? बड़ा मुद्दा यह है कि सिम्यूटर जैसे उपकरण कर ही वया सकते हैं जब कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं। सिम्यूटर की माइक्रो बैंकिंग एप्लीकेशन कर ही वया सकती है जब हमारे गांवों में माइक्रो फाइनेंस प्रणाली का कोई अता पता ही नहीं है (महाराष्ट्र तथा गुजरात के सहकारी संघ इसके अपवाद हैं)।

स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के संकलन से वया लाभ हो सकता है जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली या तो बर्बाद हो रही है या फिर अधिकांश जगहों पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप सिम्यूटर के इस्तेमाल के जरिए स्वास्थ्य संबंधी बेहतर आंकड़ें उपलब्ध भी कर लेते हैं तो जब तक सरकारी बाबू इन आंकड़ों के उपयोग का तरीका ही नहीं जानते, तब तक इस सबका उपयोग ही वया है?

निश्चित रूप से इसमें सिम्यूटर या इसको विकसित करने वालों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हमें एक बेहतर उपकरण दिया है। अब यह हमारे उपर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल की बात की जोह रही प्रौद्योगिकी का यह एक अद्भुत उदाहरण है। यह प्रश्न केवल सिम्यूटर तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह मामला तो पूरे सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जुड़ा है।

सिम्यूटर शून्य में काम नहीं कर सकता। अगर इसकी कीमत वर्तमान का दसवां हिस्सा भी अर्थात एक हजार रुपए भी हो जाए, तब भी इसे लेना मुश्किल होगा। तब भी गांववालों के लिए यह एक महंगा खिलौना ही बना रहेगा। जबतक हम आवश्यक ‘कॉटेट’ का विकास करने में समर्थ नहीं होते या उन्हें विकसित नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान काम-काज से संबंधित ‘एप्लीकेशन’ का निर्माण नहीं करते और इन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विकासोन्मुखी एजेंसियों के साथ काम नहीं करते, यह उपयोगी साबित नहीं हो सकता।

लेकिन सिम्यूटर और इंटरनेट को आम ग्रामीण के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यदि इंटरनेट पर स्थानीय रोजगार संबंधी सूचनाएं, विभिन्न सरकारी सहायता वाली स्क्रीमों की जानकारी, स्थानीय बाजार भाव, मौसम और खेती संबंधी सूचनाएं आदि मिल जाएं तो निश्चित ही यह ग्रामीणों के लिए उपयोगी होगा। इंटरनेट की सार्थकता तभी पूरी होगी जब वह ग्रामीणों की जरूरत वाले सरकारी विभागों से जुड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी को जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिए तो वह उसे इनफार्मेशन किओस्क के माध्यम से गांव में ही मिलाया चाहिए और फिर तहसील ऑफिस कोई अर्जी भेजनी हो या खसरा-खतौनी (जमीन रिकार्ड) की कोई जानकारी चाहिए हो इनफार्मेशन किओस्क से यह काम आसानी से हो सकता है। लेकिन इसके लिए स्थानीय सरकारी विभागों को तैयार करना होगा, उनके रिकार्ड्स कम्प्यूटरीकृत करने होंगे।

वैज्ञानिकों ने गांवों में विजली और टेलीफोन जैसी मूल सुविधाओं के अभाव के वक्रमूह को तोड़ने का जोर देने का भी काम है। सिम्यूटर और इंटरनेट के लिए एस्टेबलिशमेंट टेक्नॉलॉजी के रूप में वैज्ञानिकों ने गांवों में जरूरत की सूचनाएं और सेवाएं पहुंचाने का एक नया सस्ता दिखवाया है। इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, यह समाज को निश्चित करना है।

स्थिति साफ है। टेक्नॉलॉजी संसाधनों की कमी को पूरा नहीं कर सकती, बल्कि उपलब्ध संसाधनों के पूरे और सही उपयोग में सार्थक भूमिका निभा सकती हैं सूचना की कमी से होने वाली दिक्कों को दूर कर सकती है। प्रशासकों, जन प्रतिनिधियों और जनता के बीच निरंतर संवाद का एक जरिया बन सकती हैं। सूचना के अधिष्ठान जैसे कालूनों की एक नया अर्थ दे सकती है। ग्रामीणों को नए हुनर सिखा सकता है, उनके उत्पादों में लिए गए बाजार खोल सकती है । आईसीटी के उपयोग से निश्चित ही हमारे गांवों में शिक्षा का स्तर उंचा उठाया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, आम आदमी और जिला प्रशासन के बीच की दूरी कम भी हो सकती है। टेक्नॉलॉजी विकास के लिए ज़रूरी माहौल बना सकती है।

संभावनाएं अपार हैं। चीन के कम्प्युनिस्ट नेता दंग जिआओ पेंग ने विकास के संदर्भ में कहा था कि लोगों को मछली नहीं, मछली पकड़ने की छड़ी दो (गिव देम फिशिंग रॉड, नाट फिश)। आईसीटी को हम मछली समझे या मछली पकड़ने की छड़ी, नतीजा इस पर निर्भर करेगा। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई की तरह, एक “डिजिटल डिवाइड” खड़ी हो जाएगा।

कर्नाटक की “भूमि” परियोजना आज भारत में सूचना तकनीकी के जमीनी स्तर पर प्रयोग की पहली पूरी तरह कार्यरत योजना है। इसके चलते राज्य के लोगों को अपने भूमि रिकार्ड या पट्टे की ‘नकल’ पाने के लिए विचौलियों की मदद नहीं लेनी पड़ती। और न ही किसी अर्जी की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर लोग जमीन खरीदने से पहले उसका पट्टा देखना चाहते हैं। अब ये लोग सीधे तालुका दफत में जाते हैं, यहाँ पर रवागत क्षेत्र में ही एक कम्प्यूटर रखा है। इसका कोई की-बोर्ड नहीं है। स्क्रीन पर स्पर्श कर के सारा काम हो सकता है। जिस जमीन का रिकार्ड आपको देखना है उसका सर्वे नंबर इस कम्प्यूटर पर अंकित कीजिए, और कुछ सेकेंड्स में सारा रिकार्ड स्क्रीन पर होगा। और यदि इस रिकार्ड की कम्प्यूटर चालते हैं तो एक और स्पर्श कीजिए, साथ आपले कंधा में रखे प्रिंटर पर सारा रिकार्ड छप जायेगा। १५ रुपए जमा कीजिए और अपने भूमि रिकार्ड की छपी हुई कॉपी आपके हाथ में होगी। पहले भूमि रिकार्ड की नकल लेने में कई-कई दिन लग जाते थे। यह पूरी तरह गांव के पटवारी के मूड पर निर्भर था। और किसी भी हालत में “दान दक्षिणा” तो देनी ही पड़ती थी।

राज्य के सभी १७७ तालुकाओं में सभी भूमि रिकार्ड्स कम्प्यूटरीकृत कर दिए गये हैं। और एक ऐसी व्यवस्था बनाई भी हुई है जिससे एक रिकार्ड्स तुरंत लोगों को उपलब्ध कराए जा सकें। यह सारा काम “भूमि” नाम की परियोजना के तहत हुआ है। कर्नाटक में २७ जिले हैं, जो १७७ तालुकाओं में बंटे हैं और कुल गांवों की संख्या २९,००० है। पूरे राज्य में लगभग दो करोड़ किसानों के १.७ करोड़ भूमिरिकार्ड हैं। और हरेक रिकार्ड में जमीन का मालिकाना हक, किराएदार, उपज की स्थिति, पेड़ों की संख्या, मिट्टी का प्रकार सभी जानकारियां दर्ज हैं। “भूमि” योजना के अंतर्गत इन सारे रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। जिस प्रकार से ये रिकार्ड आज तक रखे जाते थे, उसमें बिना किसी बदलाव लाए कम्प्यूटरीकृत किया गया ताकि इन्हे समझने में कोई कठिनाई न हो। वृत्ति के हर रिकार्ड की प्रतीक भी कभी कभी की जानकारियां होती हैं, कंप्यूटर में कुल “एंट्रीज” की संख्या २० करोड़ थी। इस काम में गांव के पटवारियों की भी मदद ली गई। और इस काम दो साल में निपटाया गया। इस प्रकार हर तालुके का एक डाटाबेस बना जिसमें इस तालुके के सभी भूमि रिकार्ड शामिल थे।

“भूमि” योजना को भारी सफलता मिली है। योजना करीब २०,००० किसान इसका फायदा उठाते हैं। और १८ महीन के भीतर इस योजना से १२ करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि पूरी परियोजना पर पूरा खर्च १८ करोड़ रुपए हुआ था। वृत्ति सभी भूमि रिकार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध है, सभी कागजी रिकार्ड बाकायदा नष्ट कर दिए गए हैं। एक सरकारी आदेश द्वारा जमीनी रिकार्डों में कहीं भी हाथ की लिखाई को गैर कानूनी करार दिया गया है।

परियोजना का सारा सॉफ्टवेयर कन्नड़ में विकसित किया गया। किसान को केवल टच स्क्रीन के साथ लगे नंबर पैड से सर्वे नंबर अंकित करना होता है। बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। “भूमि” के रिकार्डों में बदलाव केवल अधिकृत अधिकारी ही कर सके इसके लिए अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली प्रयुक्त की गई है। इसे “बायो मेट्रिक्स” कहते हैं। केवल “पासवर्ड” मात्र से डाटाबेस नहीं खुलता। अधिकृत अधिकारी को अपने अंगूठे का निशान कम्प्यूटर को दिखाना होता है (एक विशेष प्रकार के माउस के जरिए) तभी वह डाटाबेस में परिवर्तन दर्ज कर पाता है।

इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों के लिए इसे एक आदर्श योजना घोषित किया है। लेकिन भ्रमाफिजाओं के दबाव में चल रही कुछ सरकरें शायद ही “भूमि” को अपनाएंगी। जाहिर है “भूमि” जैसी योजना लागू करने के लिए मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिए। यहाँ नई टेक्नॉलॉजी कुछ नहीं कर सकती।